

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEASI TIMES

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स
इन इंडिया



www.ceasi.in

@ceasi_india



हमारे बारे में

हम कौन हैं:

“सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)” एक स्वायत्त संस्था है, जो “एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)” के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशल युक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- 15+ राज्य
- 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया



CEASI TIMES

फार्म मेकनजेशन इनसाइट्स



केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पटियाला में कृषि यंत्र फैक्ट्री का दौरा किया

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत पंजाब के पटियाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की, खेतों का निरीक्षण किया और अमरगढ़ स्थित एक कृषि यंत्र फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अब भारत आधुनिक कृषि यंत्रों का निर्माण खुद कर रहा है, जो देश में उपयोग के साथ-साथ निर्यात के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं।

श्री चौहान ने छोटे किसानों के लिए सस्ते यंत्रों की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि सब्सिडी केवल पात्र लोगों को ही दी जानी चाहिए। उन्होंने बोवाई और कटाई जैसे कामों के लिए मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही ताकि लागत और श्रम में कमी आ सके। साथ ही, उन्होंने जलवायु-रोधी बीजों और तकनीकों को अपनाने की सलाह दी।

श्री चौहान ने पंजाब के किसानों की देश को अन्न प्रदान करने में अहम भूमिका की सराहना की और कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत आधारशिला है। उन्होंने राज्यों, वैज्ञानिकों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने की अपील की ताकि खेती को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाया जा सके। अंत में, उन्होंने भारत को कृषि नवाचार और मशीनीकरण में अग्रणी बनाने का आह्वान किया।

भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय एग्री हैकाथॉन पुणे में संपन्न

भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय एग्री हैकाथॉन पुणे में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य तकनीक के माध्यम से कृषि को बेहतर बनाना था। इस कार्यक्रम में किसानों, स्टार्टअप्स, छात्रों और विशेषज्ञों ने भाग लिया और खेती के लिए स्मार्ट व व्यावहारिक समाधान खोजने पर चर्चा की। समापन समारोह में वक्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के खेती पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित किया और किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों और नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया।

नई 'लैब टू लैंड' नीति के तहत देशभर के 16,000 कृषि वैज्ञानिकों को सीधे किसानों से जोड़ने की योजना है, ताकि उपयोगी तकनीकों को खेतों तक पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंचाई, मशीनीकरण और बाजार से जुड़ाव जैसे विषयों पर सर्वश्रेष्ठ एग्री-टेक आइडियाज को पुरस्कृत किया गया, जिससे भारतीय कृषि के उज्ज्वल भविष्य की झलक मिली।

वक्ताओं ने इन समाधानों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। एक बड़ी घोषणा के रूप में 'क्लीन प्लांट' कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत किसानों को रोगमुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र में तीन प्रमुख केंद्र बनाए जाएंगे— अंगूर के लिए पुणे, संतरे के लिए नागपुर, और अनार के लिए सोलापुर में— जहां आधुनिक नर्सरियों को सहयोग मिलेगा।



CEASI TIMES

कॉनकण एग्री-टेक सम्मेलन में फार्म मशीनीकरण पर जोर

महाराष्ट्र स्टेट मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन (MSMGA) ने रायगढ़ जिले के सहान, अलीबाग में एक सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य कोकण क्षेत्र के किसानों को बदलते जलवायु परिस्थितियों से निपटने में मदद करना था। कार्यक्रम में टिकाऊ खेती और फसल हानि को कम करने के लिए व्यावहारिक तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया गया।



फार्म मशीनीकरण इस आयोजन का मुख्य विषय रहा, जहां बागवानी, सिंचाई और प्रसंस्करण से जुड़ी तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। छोटे और मध्यम किसानों के लिए डिजाइन किया गया इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जो ईंधन लागत को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों ने स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल मशीनें प्रदर्शित कीं।

ड्रोन तकनीक का प्रयोग फसल निगरानी और स्प्रींग के लिए किया गया। MSMGA अध्यक्ष ने मौसम से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और पैदावार बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सहित अधिकारियों ने फसल बीमा जैसी निरंतर सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। यह कार्यक्रम जलवायु-लचीली खेती के लिए मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।



गोवा में धान की खेती के लिए ड्रोन उपयोग की शुरुआत

गोवा के किसान इस खरीफ सीजन में मजदूरों की कमी और लागत को कम करने के लिए तेजी से मशीनीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव में ड्रोन का उपयोग अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन चिंचिनिम और सालसेट जैसे क्षेत्रों में प्रारंभिक प्रयास सकारात्मक परिणाम दिखा रहे हैं। स्थानीय सफलता की कहानियों और जागरूकता के साथ गोवा धीरे-धीरे आधुनिक, तकनीक-आधारित और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ रहा है।

‘गोएंचो खेतकार’ नामक स्थानीय किसान समूह, जो फातोर्डा के डॉन बॉस्को से फ्र जॉर्ज क्वार्ट्रॉस के नेतृत्व में है, ने गोवा में कृषि में ड्रोन के उपयोग की शुरुआत की है। इनकी प्रभावी छिड़काव पद्धतियाँ किसानों को समय बचाने और केवल प्रभावित क्षेत्रों पर कीटनाशक छिड़क कर रसायनों की खपत कम करने में मदद कर रही हैं। जो काम पहले एक सप्ताह में होता था, अब एक ही दिन में संभव है।

कृषि विभाग ड्रोन के व्यापक उपयोग की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है और अधिक किसानों, खासकर महिला स्व-सहायता समूहों को केंद्र सरकार की ‘ड्रोन दीदी योजना’ के तहत ड्रोन खरीद पर 80% तक की सब्सिडी का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।

CEASI TIMES

हॉर्टिकल्चर इनसाइट्स



उत्तराखंड बनेगा बागवानी का राष्ट्रीय केंद्र

उत्तराखंड को बागवानी के क्षेत्र में राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ठोस प्रयास कर रही हैं। राज्य के विशेष उत्पाद—जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फल, अनाज और सब्जियां—वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। अधिकारियों ने आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच बढ़ाने और बीज, सिंचाई, विपणन व फसल बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को मजबूत सहायता प्रदान करने पर जोर दिया।

हाल ही में हुई एक संवाद बैठक में लीची, बासमती चावल, कटहल और सब्जियां उगाने वाले किसानों के साथ सीधा संवाद कर जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया।

चर्चा में किसानों की सक्रिय भागीदारी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, जल संरक्षण और नई तकनीकों को अपनाने जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई। एक वृक्षारोपण अभियान ने टिकाऊ और हरित कृषि की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

महाराष्ट्र में बागवानी को बढ़ावा: केंद्र सरकार ने ₹300 करोड़ की घोषणा की

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए तीन अत्याधुनिक बागवानी केंद्र स्थापित करने के लिए ₹300 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। ये उन्नत केंद्र पुणे, नागपुर और सोलापुर जैसे प्रमुख जिलों में बनाए जाएंगे, जहां पर अंगूर, संतरा और अनार जैसी महत्वपूर्ण फसलों के लिए बीमारी-मुक्त और गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जाएंगे।



इस योजना का उद्देश्य किसानों को अच्छी क्वालिटी की पौध उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी फसल का उत्पादन और आमदनी दोनों बढ़ें। महाराष्ट्र पहले से ही अंगूर, अनार, संतरा और सब्जियों की खेती में आगे है।

'क्लीन प्लांट प्रोग्राम' के तहत देश में कुल 9 ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे ताकि किसानों को भरोसेमंद और स्वस्थ पौधे मिल सकें। यह जानकारी एक कृषि नवाचार कार्यक्रम के दौरान दी गई, जिसमें यह भी बताया गया कि कैसे तकनीक के इस्तेमाल से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

CEASI TIMES

उत्तर प्रदेश में वैश्विक तकनीक से कृषि नवाचार को नई दिशा

उत्तर प्रदेश कृषि नवाचार के क्षेत्र में तेज़ी से अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। राज्य में मिर्जापुर, बुंदेलखंड और बाराबंकी में इंडो-इसाइल-डच सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र ड्रैगन फ्रूट, खट्टे फल और फूल-सब्जियों की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों और उन्नत वैश्विक खेती की तकनीकें अपनाने में मदद करते हैं।



ये केंद्र किसानों को प्रशिक्षण देने वाले हब के रूप में काम करेंगे, जहां रोपाई से लेकर कटाई के बाद की तकनीकों तक आधुनिक तरीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे किसान अपनी उपज में विविधता ला सकेंगे और मुनाफा बढ़ा सकेंगे। उत्तर प्रदेश उत्कृष्टता केंद्रों में अंतरराष्ट्रीय तकनीक के उपयोग के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है।

राज्य में फलों, सब्जियों, शहद और एरोपोनिक आलू के लिए छह नए केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य 150 स्थानों पर सालाना 28 करोड़ गुणवत्तापूर्ण पौधों का उत्पादन करना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आम की खेती में नवाचार और जेवर के पास एक परीक्षण एवं उपचार पार्क की स्थापना की जा रही है, जिससे टिकाऊ और निर्यात-उन्मुख कृषि को बढ़ावा मिलेगा।



बिहार की सहकारी योजना से दुबई को सब्जी निर्यात की शुरुआत

बिहार ने दुबई को सब्जियां निर्यात करना शुरू कर दिया है। यह काम नए बने सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन, VEGFED के जरिए किया जा रहा है, जो राज्य की डेयरी सहकारी व्यवस्था की तरह है। पहली बार 1,500 किलो कटहल, फूलगोभी, बैंगन, करेला और लौकी वारणसी से दुबई के लुलु मॉल भेजी गई। बिहार तिरहुत, मगध, वैशाली और चंपारण में किसानों की सहकारी समितियों के माध्यम से सब्जी उत्पादन और वैश्विक बाजार को बढ़ावा दे रहा है।

VEGFED का मकसद किसानों को घरेलू बाजार की तुलना में 20 गुना ज्यादा लाभ देना है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकें। दुबई से 45 मीट्रिक टन सब्जियों की मांग पहले ही मिल चुकी है और अगली खेप सिंगापुर के लिए भेजी जाएगी। बिहार में 534 'तरकारी' रिटेल आउटलेट स्थापित करने की योजना है, जिनमें से 200 के लिए जमीन भी मिली है।

VEGFED की समितियां 495 ब्लॉकों और चार यूनियनों में बन चुकी हैं और जल्द ही पूरा क्षेत्र कवर होगा। यह योजना डेयरी सहकारियों की सफलता को सब्जी क्षेत्र में दोहराने का प्रयास है, जिससे किसानों की आय और बाजार पहुंच दोनों बढ़ें।

CEASI TIMES

डेयरी इनसाइट्स



उत्तर प्रदेश में डेयरी एफपीओ बनाएंगे, सीधे उत्पादकों से दूध खरीदा जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार दूध उत्पादकों के समर्थन के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत डेयरी किसानों के लिए प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) स्थापित किए जाएंगे, जिससे गांव स्तर पर किसानों से सीधे उचित कीमत पर दूध खरीदा जा सकेगा। यह घोषणा पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने नंद बाबा मिल्क मिशन कार्यालय और मिल्क डेवलपमेंट पोर्टल के शुभारंभ के दौरान की।

पिछले पांच वर्षों में नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत डेयरी क्षेत्र में ₹1,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2023-24 में पांच जिलों में पायलट डेयरी एफपीओ प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी, उत्पादक डेटाबेस, देशी नस्लों को बढ़ावा और किसान प्रोत्साहन शामिल होंगे।

राज्य और जिला स्तर पर समितियां परियोजना की प्रगति की निगरानी करेंगी। साथ ही, किसानों को पशु रोग जांच किट और दूध मिलावट जांच किट भी दी जाएगी ताकि उत्पाद की गुणवत्ता और पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। ये प्रयास डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हैं।

हिमाचल प्रदेश ने किसानों के समर्थन के लिए दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) शुरू किया

हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू किया है। यह कदम पशुपालन किसानों का समर्थन करने और ग्रामीण आजीविका सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार रोजाना 2.32 लाख लीटर से ज्यादा दूध खरीदती है, जिसमें गाय के दूध के लिए ₹51 प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए ₹61 प्रति लीटर दिया जाता है। हिम गंगा योजना के तहत हमीरपुर और कांगड़ा में 268 नई डेयरी सहकारी समितियां बनीं, जिनमें से 110 पंजीकृत हैं।



हमीरपुर की 20 समितियों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जो समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही हैं। बकरी के दूध की खरीद का भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें ₹70 प्रति लीटर की कीमत मिलती है और 15 किसानों से रोजाना 100 लीटर दूध संग्रहित किया जाता है। सहकारी समितियों के लिए परिवहन सब्सिडी ₹3 प्रति लीटर कर दी गई है, जिसे ₹6 करोड़ वार्षिक कोष से समर्थित किया गया है। ये पहल डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और राज्य में सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए हैं। इस योजना से 38,000 से अधिक गाय दूध सप्लायर और लगभग 1,500 भैंस पालक लाभान्वित हो रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाने हेतु ₹2 प्रति लीटर की परिवहन सब्सिडी भी मिलती है।

CEASI TIMES

राजस्थान में पशु मेलों का आयोजन: पशुपालन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा

राजस्थान सरकार केंद्र के साथ मिलकर विभागीय स्तर और 11 और जिलों में पशु मेला आयोजित करने जा रही है। इसका उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाना है। देवस्थान और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के अनुसार, इन मेलों में पशुपालकों को अच्छे नस्लों के जानवर और नस्ल सुधार कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी।



राजस्थान में 4,000 से ज्यादा गौशालाएं और नंदीशालाएं हैं। उच्च बैल संख्या की समस्या से निपटने के लिए मेलों को 7 से बढ़ाकर 44 जिलों तक फैलाया जाएगा। इसका मकसद सेवा पहुँच और पशु गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। ये प्रयास राज्य के पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की नई दिशा हैं।

ब्राजीलियन गिर गाय के वीर्य पर सब्सिडी दी जाएगी, जो रोजाना 40-50 लीटर दूध देती है। सेक्स-सॉर्टेड सीमेंट योजना के तहत 90% संभावना है कि बच्चे मादा होंगे, जिससे उत्पादन बढ़ाने और ब्रीडर्स का समर्थन करने में मदद मिलेगी।



एपीईडीए और डीएएचडी ने पशुधन व मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात बढ़ाने पर राउंडटेबल आयोजित

एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बैंडरी एंड डेयरींग (DAHD) ने नई दिल्ली में "पशुधन और उनके मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्यात - भविष्य की संभावनाएँ और आगे का रास्ता" विषय पर संयुक्त राउंडटेबल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता DAHD सचिव अल्का उपाध्याय ने की, जिसमें अधिकारी, विशेषज्ञ और उद्योग के प्रमुख उपस्थित हुए और भारत के पशुधन निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

मुख्य ध्यान क्षेत्र थे: रोग नियंत्रण, नौ राज्यों में एफएमडी-मुक्त अवसंरचना, ट्रेसबिलिटी, गुणवत्ता प्रणालियाँ और बेहतर बाज़ार पहुँच। चर्चा में पशुधन निर्यात में 20% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया, निर्यात इकाइयों के लिए स्टार रेटिंग्स को बढ़ावा दिया गया, और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने व स्वच्छ प्रसंस्करण पर जोर दिया गया।

कार्यशाला में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच सहयोग और व्यापार समझौतों के उपयोग पर बल दिया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में पशु उत्पादों का निर्यात 5.1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। चर्चा का मुख्य उद्देश्य भारत को पशुधन और मूल्य संवर्धित उत्पादों का एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनाने के लिए रणनीतिक रोडमैप तैयार करना था।

CEASI TIMES

जनरल एग्रीकल्चर इनसाइट्स



भारत-अमेरिकी व्यापार वार्ताओं में किसानों के हितों की रक्षा करेगा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत अमेरिका के साथ चल रही महत्वपूर्ण कृषि व्यापार वार्ताओं में अपने सभी किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा और रक्षा करेगा। दोनों देश वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार को बेहतर और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत किसी भी समझौते को अंतिम रूप देने से पहले इसके संभावित लाभ और चुनौतियों का गहन और ध्यानपूर्वक आकलन करेगा ताकि हमारे कृषि समुदाय का उचित संरक्षण हो सके।

चौहान ने यह भी जोर दिया कि भारत किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखे बिना कोई फैसला नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी समझौता संतुलित और न्यायसंगत हो। इन वार्ताओं का उद्देश्य 2025 के शरद ऋतु तक द्विपक्षीय समझौते के पहले चरण का रूपरेखा तैयार करना है।

भारत अमेरिका को बासमती चावल और मसाले जैसे उत्पाद निर्यात करता है, जबकि अमेरिका भारत को मक्का, सोयाबीन और पशु आहार के निर्यात में वृद्धि करना चाहता है। हालांकि, उच्च शुल्क और भारत की कृषि एवं डेयरी बाजारों को पूरी तरह खोलने में सतर्कता अभी भी मुख्य चुनौतियां बनी हुई हैं।

पीएसीएस के लिए ऋण सहायता से खाद्य भंडारण नेटवर्क को मजबूती

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज (पीएसीएस) को लोन सुविधाओं का विस्तार करने का आग्रह किया है। इस कदम का उद्देश्य पीएसीएस को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें भारत के सहकारी खाद्य अनाज भंडारण नेटवर्क में अधिक गहराई से शामिल करना है, जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

इस योजना में राज्य स्तर पर और अधिक पीएसीएस को शामिल करना और उन्हें स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के साथ जोड़कर एक पूर्ण सहकारी आपूर्ति श्रृंखला बनाना शामिल है। शाह ने कहा कि यह पहल जीडीपी विकास और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देती है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' और 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्यों के अनुरूप है।

समीक्षा बैठक में, शाह ने इस योजना में पीएसीएस की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे वित्तीय स्थिरता और सामाजिक लाभ दोनों सुनिश्चित हो सकें।

उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गोदामों का नक्शा तैयार करने का निर्देश दिया और एफसीआई, नाफेड, तथा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जैसी एजेंसियों से पीएसीएस को मौजूदा संरचना से जोड़ने का आग्रह किया।



CEASI TIMES

गोवा में अब फसल उत्पादन का आकलन डिजिटल सिस्टम से

गोवा कृषि विभाग ने फसल उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने के लिए केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित आधुनिक डिजिटल प्रणाली को अपनाया है। इस प्रणाली में मोबाइल ऐप के माध्यम से रीयल-टाइम डेटा एंट्री, सत्यापन के लिए जीपीएस टैग की गई तस्वीरें, त्रुटियों को कम करने के लिए स्वचालित प्लॉट चयन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत वेब डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं शामिल हैं।



इस पहल के तीन चरण हैं: जिला स्तर पर योजना बनाना और नमूना चयन, खेतों में फसल कटाई प्रयोग करना और ऑटोमेटेड विश्लेषण के ज़रिए उत्पादन अनुमान तैयार करना। किसानों और अधिकारियों को इस नई प्रणाली पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह प्रणाली प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कृषि निगरानी के लिए विश्वसनीय व समय पर डेटा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे (डीजीसीईएस) पुराने मैनुअल तरीकों की जगह ले रहा है, जिससे प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और अधिक भरोसेमंद बन रही है। अब तक 60 धान और 6 गन्ने के खेतों का सर्वे किया जा चुका है, और रबी फसलों जैसे दालें, मूंगफली और सब्जियों का मूल्यांकन जारी है।



दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से कृषि नवाचार बढ़ाने हेतु नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च

एक नई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर (ISSCA) लॉन्च की गई है ताकि ग्लोबल साउथ देशों में इनोवेशन और कोलैबोरेशन को बूस्ट किया जा सके। इसका उद्देश्य प्रूवन सॉल्यूशंस को स्केल करना, नॉलेज एक्सचेंज को प्रमोट करना, और पार्टनरशिप्स बिल्ड करना है ताकि शेयर्ड एग्रीकल्चरल चैलेंजेज़ का समाधान हो सके। इस दिशा में एक स्ट्रेटेजिक MoU सिंग किया गया है ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को शARED एक्सपर्टाइज और कैपैसिटी बिल्डिंग के माध्यम से प्रमोट किया जा सके।

ISSCA में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जो वैलिडेटेड इनोवेशनस् का रिपॉजिटरी है, पीयर लर्निंग को सपोर्ट करता है, और ड्राइलैंड और डेवलपिंग रीजंस के लिए अफॉर्डेबल टेक्नोलॉजीज़ प्रमोट करता है। यह ग्लोबल साउथ में इनक्लूसिव एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट, एक्शन, और पार्टनरशिप्स के माध्यम से फॉस्टर करता है।

यह सेंटर क्लाइमेंट-स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेज़ को भी सपोर्ट करेगा, जिसमें सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन शामिल है, ताकि पार्टनर कंट्रीज़ में रेसिलिएंट और प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को कन्क्रिटली कंट्रीब्यूट किया जा सके।

CEASI एक्टिविटीज

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया : अयोध्या में सतत गन्ना खेती को बढ़ावा

शाश्वत मिठास परियोजना के अंतर्गत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया , UPL SAS Limited के सहयोग से अयोध्या में सतत गन्ना खेती की प्रथाएँ लागू कर रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच इको-फ्रेंडली खेती तकनीकों का ज्ञान और कौशल बढ़ाना है। इस दिशा में एक समर्पित टीम मौजूदा कृषि प्रथाओं का मूल्यांकन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान के लिए खेत सर्वेक्षण कर रही है।

साथ ही, खेत स्तर पर डेमो प्लॉट स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ गन्ना की सतत खेती के तरीके प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन प्रक्षेत्र किसानों को जल प्रबंधन, मिट्टी स्वास्थ्य सुधारने तथा जैविक उर्वरकों के उपयोग जैसी बेहतर प्रथाएँ अपनाने के लिए व्यावहारिक उदाहरण देंगे। इन पहलों के माध्यम से परियोजना का लक्ष्य स्थानीय किसानों में बेहतर उपज और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

हमने विश्व पर्यावरण दिवस पर अयोध्या जिले में पेड़ लगाए और मिट्टी संरक्षण, सूक्ष्मजलवायु नियंत्रण तथा दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता के लिए पेड़ों के महत्व को रेखांकित किया। इन प्रयासों का उद्देश्य सतत कृषि के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय किसानों को व्यावहारिक सीख प्रदान करना है।



CEASI एक्टिविटीज

क्लस्टर फार्मिंग और बागवानी प्रबंधन प्रशिक्षण के माध्यम से करनाल में महिला किसानों को सशक्त बनाना

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI) ने एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित HP-SHIVA परियोजना के अंतर्गत 30 महिला किसानों को लक्षित करते हुए 26 से 28 मई तक करनाल में एक 3-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण-सह-अभ्यास कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह प्रशिक्षण क्लस्टर फार्मिंग, एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) विकास और बागवानी प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास और सतत कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करके सशक्त बनाना है।

इस पहल के तहत प्रतिभागियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें सैद्धांतिक सत्र, व्यावहारिक प्रशिक्षण, रोलप्ले और उन्नत तकनीकों से परिचय शामिल था। इसके साथ ही, कुरुक्षेत्र स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और लाडवा स्थित उप-उष्णकटिबंधीय फल केंद्र का दौरा भी करवाया गया, जिससे प्रतिभागियों को परागण प्रबंधन, सतत बागवानी प्रथाओं और सामूहिक खेती के तरीकों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला किसानों को आवश्यक ज्ञान, तकनीकी कौशल और आत्मविश्वास से लैस करना है ताकि वे अपने समुदायों में नवाचारी और व्यावहारिक कृषि तकनीकों को अपनाकर दीर्घकालिक कृषि स्थिरता और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दे सकें।

